गोरखपुर से प्रकाशित

RNI Reg. NO. UPBIL/2023/87841

साप्ताहिक

स्वदेशी इनक्रेडिबल

Web:www.sinews.in/E-mail: info@sinews.in

सिर्फ सच के साथ...

वर्ष : 02 अंक : 9 गोरखपुर रविवार 18 अगस्त 2024 पृष्ठ : 8 मूल्य 02 रूपया

कोलकाता हत्याकाण्ड पर सुप्रीम निर्देश, शीर्ष कोर्ट ने कहा–

न्याय व चिकित्सा को रोक नहीं सकते

नई दिल्ली। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद से जुड़ा एक वाकया भी बताया। उन्होंने बताया कि वह एक बार एक सार्वजनिक अस्पताल के फर्श पर सोए थे, जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस से जमकर सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्यबल को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करते समय सभी हितधारकों की बात सुनने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से सामान्य कामकाज बहाल का निर्देश दिया और कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता।

इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दें और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा।

दरअसल, सुनवाई के दौरान एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि उनके विरोध के कारण अब उन पर हमला किया जा रहा है। उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और अगर वे ड्यूटी पर नहीं हैं तो कानून का पालन किया जाएगा। उन्हें पहले काम पर लौटने के लिए कहें। कोई भी डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उसके बाद कोई परेशानी होती है तो हमारे पास आएं, लेकिन पहले उन्हें काम पर लौटने दें।

वहीं, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स की ओर से दलील दी गई कि डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। वे सुबह एक घंटे रैली करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं, लेकिन वे भी परेशान किया जा रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि इन संस्थानों को चलाने वाले अनुभवी निदेशक कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डाक्टर्स ने कहा कि उनकी छुट्टियां काटी जा रही हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि एक बार जब डॉक्टर्स काम पर वापस आ जाएंगे तो हम अधिकारियों पर दबाव डालेंगे कि वे प्रतिकूल कार्रवाई न करें अन्यथा अगर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे चलेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस अदालत से मिलने वाले आश्वासन से डॉक्टर्स को संतुष्टि मिलनी चाहिए। ब्श्प ने कहा कि हमने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस व्यापक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का मकसद यह है कि सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। यदि आप हमारे आदेश को देखें तो हमने वास्तव में उसी पहलू को उजागर किया है कि सार्वजनिक अस्पतालों की एक ढर्रे पर काम होता है।

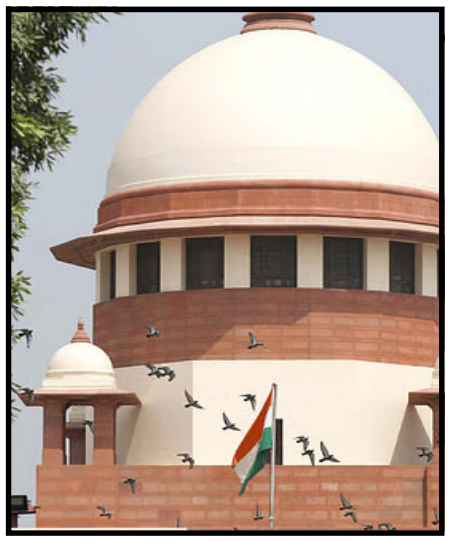

सीएम योगी बोले : हिंदू कोई जाति, मत और मजहब नहीं, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, इसमें संकीर्णता की जगह नहीं

लखनऊं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्व सीएम स्व. कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित शहिंदू गौरव दिवसश कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब हम लोग श्बाबू जीश (कल्याण सिंह) की तीसरी पुण्यतिथि को शहिंदू गौरव दिवसश के रूप में मना रहे हैं तो हमें हिंदू एकता के महत्व को भी समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति, मत और मजहब नहीं है। यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। यह भारत की सुरक्षा, एकता और एकाग्रता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखना होगा जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन यह एकता खंडित होगी उस दिन भारत को फिरके–फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल हो जाएंगी।

राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है। जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे, चाल और चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ,दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगे की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर मिला है, इन्होंने हिंदुओं के नायकों को अपमानित किया है। मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के संघर्षों और चुनौतियों की यात्रा को शिखर से शून्य की यात्रा करार देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति कल्याण सिंह अचानक नहीं बन जाता। उनकी तरह बनने के लिए संघर्ष, चुनौती, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। कल्याण सिंह ने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से कतई नहीं हटे।

मायावती ने एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के फैसले के विरोध में भारत बंद के सफल होने पर दी बधाई

लखनऊ। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के एससीध्एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में बसपा की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इसके सफल होने की सभी को बधाई दी है। बसपा की मुखिया मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के एससीध्एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में बसपा की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इसके सफल होने की सभी को बधाई दी है, किन्तु कांग्रेस–सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से इनकी जातिवादी सोच को प्रमाणित किया है। मायावती ने कहा कि कल बंद के दौरान पटनाधबिहार में निर्दोष लोगों पर पुलिस की हुई लाठीचार्जध्बर्बरता अति–दुखद व निन्दनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे और केन्द्र सरकार 'भारत बंद' के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान भी करे।

लेह में भीषण हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, छह लोगों की मौत, 19 घायल

लेह । लेह के दुर्गुक इलाके में गुरुवार को एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें छह लोगों के मारे जाने की शुरुआती जानकारी आ रही है। वहीं करीब 19 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। लेह के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घायलों को सेना और सीएचसी तांगत्से स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। बस में लगभग 25 यात्री सवार थे, जिनमें दो बच्चे और 23 स्कूल के कर्मचारी थे। यह बस एक कर्मचारी की शादी में शामिल होने के लिए डुरबुक जा रही थी, तभी डुरबुक मोड के पास यह एक गहरी खाई में जा गिरी।

पोलैंड में बोले पीएम मोदी- हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, यूक्रेन संघर्ष के दौरान मदद के लिए जताया आभार

पीएम मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं पोलैंड के पीएम के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी कहा– मैं प्रधानमंत्री टस्क के इस सुंदर शहर वारसॉ में उनके शब्दों और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका बहुत आभारी हूं। भारत–पोलैंड मैत्री को मजबूत करने के लिए आपके अमूल्य प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं। मैं आपके योगदान के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड टस्क से कहा आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है।

पीएम ने अपने संबोधन में कहा आज 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही मुझे ये सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए आपने जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते हैं।

हम मना रहे राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठश

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून का राज जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। भारत और पोलैंड अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है।

आज का दिन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण– टस्क

वहीं इससे पहले वारसॉ में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने साझा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा,आज का दिन हमारे दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम अपने देशों के बीच रणनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी कर रहे हैं।

ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, देश में दुष्कर्म की घटनाओं पर जताई चिंता, पर कोलकाता मामले का जिक्र नहीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभर में लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ममता की प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी ऐसे समय में सामने आई है, जब कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य सरकार के रवैये की लगातार आलोचना हो रही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंद्योपाध्याय ने कहा, ष्पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है – श्आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।इसी चिट्ठी में आगे कहा गया, ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो।

ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट–ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई अधिमानतः 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने किया एलान

जम्मू । कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमारी बैठक हुई। हमारी योजनाएं सही रास्ते पर हैं और हमें उम्मीद है कि गठबंधन अच्छा चलेगा। सीट बंटवारे पर हमारे बीच विचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधासनभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का एलान किया है। उन्होंने कहा कि नेकां और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया, शाम तक चरणवार सूची प्रकाशित की जाएगी। कांग्रेस ने भी अपने एक्स अकाउंट से गठबंधन की घोषणा की है। जिसमें कहा कि आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमारी बैठक हुई। हमारी योजनाएं सही रास्ते पर हैं और हमें उम्मीद है कि गठबंधन अच्छा चलेगा। सीट बंटवारे पर हमारे बीच विचार चल रहा है। आज शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

चुनाव आयुक्त ने की पर्यवेक्षकों संग बैठकजम्मू–कश्मीर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों संग बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि आज हमने तीन तरह के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है।

आगे कहा कि जिसमें सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। सामान्य पर्यवेक्षक मशीनों पर, पुलिस पर्यवेक्षक बल की तैनाती पर और व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की बैठक में कहा,

ष्आज हमने तीन तरह के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं।

बातचीत में आगे कहा कि हर उम्मीदवार के लिए पर्यवेक्षक उपलब्ध रहेंगे। सभी व्यवस्थाएं निष्पक्ष रूप से की जाएंगी। चुनावों को लेकर जम्मू–कश्मीर के लोगों में बहुत उत्साह है। हम और हमारे सभी पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग जहां चाहें वहां स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

हरियाणा में भाजपा मंत्री का बवाली बयान, कहा– कांग्रेस सरकार बनी तो हमारे दिल्ली वाले 6 माह टिकने नहीं देंगे

हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री जेपी दलाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो दिल्ली में उनकी पार्टी (भाजपा) की सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी विपक्षी सरकार छह महीने से अधिक न चले। दलाल ने यह बात मंगलवार को भिवानी जिले में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। हरियाणवी बोली में जनसभा को संबोधित करते हुए दलाल ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे खराब स्थिति में भी... दिल्ली में हमारे नेता उन्हें छह महीने से अधिक सत्ता में नहीं रहने देंगे। दलाल के भाषण का वीडियो मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दलाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा में कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि उनके बयान ने भाजपा की साजिश को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि दलाल संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं और भाजपा को उनसे पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि दलाल ने अपने बयानों से विवाद खड़ा किया हो और अपनी पार्टी को मुश्किल में डाला हो। नवंबर 2023 में दलाल ने अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को ष्सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति...ष कहा था। इससे पहले दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन के दौरान, उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि देश को अस्थिर करने के लिए किसान आंदोलन के पीछे चीन, पाकिस्तान और अन्य ष्दुश्मनष देशों सहित विदेशी ताकतें हैं।

वक्फ बिल पर JPC की पहली बैठक में बवाल! सांसदों के बीच हो गई तीखी नोकझोंक

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने गुरुवार को अपनी पहली मैराथन बैठक आयोजित की, जबकि प्रस्तावित कानून के कई प्रावधानों पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई थी। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक प्रस्तुति दी। लंबी बैठक के दौरान तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार दर्ज कराए, सुझाव दिए तथा विधेयक के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आप के संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके के ए राजा समेत विपक्षी सदस्यों ने कलेक्टर को अधिक अधिकार देने और वक्फ बोर्ड में गैर–मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे कई प्रावधानों पर सवाल उठाए। उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रालय की तैयारियों पर भी चिंता जताई गई। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि विभिन्न मुस्लिम निकायों समेत सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। समिति का लक्ष्य अगले सत्र तक सभी 44 संशोधनों को संबोधित करते हुए एक व्यापक विधेयक लाना है।सूत्रों ने बताया कि समिति में विपक्ष के कई सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो ष्असंवैधानिकष हैं और मुस्लिम समुदाय के षहितों के लिए हानिकारकष हैं। उन्होंने कहा कि इस रुख का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में उसके सहयोगियों ने भी विरोध किया, जिसके कारण तीखी बहस हुई। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि विधेयक धर्म की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। कुछ सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों की प्रस्तुति पर असंतोष व्यक्त किया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा के सहयोगियों ने कहा कि मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

लालू यादव की पार्टी राजद से श्याम रजक का इस्तीफा, मन की बात लिखकर दूसरी बार पार्टी छोड़ी

पटना। बिहार सरकार के मंत्री रहे श्याम रजक ने दूसरी बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। पिछली बार वह रजत छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद जदयू के साथ राजद की ही सरकार बनने से वह असहज हो गए थे।

उधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में इलाज करने के लिए रवाना हुए और इधर उनकी पार्टी को जोर का झटका लगा है। कभी लालू–राबड़ी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री की भूमिका निभाने वाले श्याम रजक ने दूसरी बार राजद का साथ छोड़ दिया है। पिछली बार वह राजद को छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। इस बार भी इसी तरह की संभावना दिख रही है, हालांकि उन्होंने अभी इसकी घोषणा नहीं की है।

जानिये क्या लिखा पत्र में

श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। श्याम रजक ने अंत में अपने शायराना अंदाज में शिकायत करने के साथ–साथ धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।

किस बात से श्याम रजक हुए नाराज कहा जा रहा है कि दरअसल श्याम रजक को इस बात से नाराजगी थी कि उन्हें राज्य सभा क्यों नहीं भेजा गया। उनके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल ने मनोझ झा को दोबारा राज्यसभा भेज दिया। वहीं श्याम रजक की जाति, धोबी समाज से मुन्नी रजक को विधान परिषद भेज दिया।

एक माह के अंदर होगा दुग्ध समितियों का भुगतान

दुग्ध व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सशक्त माध्यम : धर्मपाल

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्ष 2022–23 में प्रदेश के सर्वाधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता 66 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 48 दुग्ध उत्पादकों को नन्दबाबा पुरस्कार से आज यहां इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। पुरस्कृत 114 दुग्ध उत्पादकों को प्रतीक चिन्ह, पुरस्कार धनराशि प्रमाण–पत्र सहित देकर प्रोत्साहित किया गया। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से भारतीय गोवंशीय देशी गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध समितियों के माध्यम से व्यवसाय करने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर दुग्ध समितियों के दुग्ध मूल्य का भुगतान कराया जायेगा।कार्यक्रम में गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत लखीमपुर–खीरी निवासी एवं वेलवा मोती समिति के वरूण सिंह को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार और मेरठ के रहने वाले रुहासा दुग्ध समिति के हर्ष मित्तल को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इन दोनों दुग्ध उत्पादकों को क्रमशः 02 लाख रुपये एवं 1. 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि तथा शेष अन्य चयनित लाभार्थियों को जनपद स्तरीय पुरस्कार के तहत 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। नंदबाबा पुरस्कार के तहत अयोध्या निवासी उधौली दुग्ध समिति के लवलेश कुमार को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करते हुए पुरस्कार स्वरूप 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। जनपद स्तरीय पुरस्कार के तहत 21 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। श्री सिंह ने कहा कि पुरस्कृत 114 दुग्ध उत्पादकों में से 26 महिला लाभार्थी है, जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओ की भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण है। दूध प्रोसेसिंग की कमियों को दूर करने, किसानों को प्रशिक्षण देने एवं दुग्ध उत्पादन में नई तकनीक व नई जानकारी देने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में दुग्ध सहकारिता के माध्यम से पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय को कृषि के सहयोगी व्यवसाय के रुप में अपनाया जा रहा है। वर्तमान में दुग्ध व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार कासशक्त माध्यम बन चुका है। यह किसानों और पशुपालकों की आय दोगुना करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादकों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें क्रत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का लाभ तथा तकनीकी निवेश की सुविधा दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वार पर ही उपलब्ध करायी जा रही है और पशु प्रजनन, पोषण एवं प्रबन्धन का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। मोबाइल बेटनरी यूनिट द्वारा पशुओं की त्वरित चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।इस अवसर पर पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव के रविन्द्र नायक ने कहा कि दुग्ध समितियों के भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी और निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित किए जाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि गोकुल पुरस्कार के तहत दुग्ध विकस के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए गोकुल पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। गोकुल पुरस्कार के चयन के लिए वे ही दुग्ध उत्पादन पात्र होते है, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 5000 ली या इससे अधिक दूध दुग्ध समिति में आपूर्ति किया गया हो। प्रदेश की दुग्ध समिति में सर्वाधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता दुग्ध उत्पादक को प्रथम एवं द्वितीय लाभार्थी को राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा शेष को जनपद स्तरीय पुरस्कार वितरित किया जाता है।प्रमुख सचिव ने बताया कि नन्दबाबा पुरस्कार के तहत दुग्ध विकास के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नन्दबाबा पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। नन्दबाबा पुरस्कार के लिए भारतीय गोवंश की गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले वे ही उत्पादक पात्र होते हैं, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष में कम–से–कम 1500 लीटर या उससे अधिक दूध दुग्ध समिति में आपूर्ति किया गया हो।इस अवसर पर दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्र, पीसीडीएफ के प्रबन्ध निदेशक, आनंद कुमार, विशेष सचिव दुग्ध विकास विभाग राम सहाय यादव, दुग्ध संघों के निर्वाचित अध्यक्ष एवं दुग्ध संघो के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

अयोध्या में खड़ी कार का लखनऊ में चालान

लखनऊ (संवाददाता) । महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक की कार का दो बार लखनऊ में चालान कट गया, जबकि कार अयोध्या में खड़ी थी।मामले की जानकारी होने पर उपनिदेशक ने बिजनौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। ओमेक्स सिटी निवासी सर्वेश पाण्डेय उपनिदेशक के तौर पर अयोध्या में तैनात हं। सर्वेश की मां उर्मिला के नाम पर कार है। इस कार के रजिस्ट्रेशन नम्बर पर दो चालान काटे गए।पहला 26 और दूसरा 29 को काटा गया। सर्वेश के मुताबिक 26 को वह कार लेकर अयोध्या गए हुए थे। कार उनके दफ्तर की पार्किंग में खड़ी थी। 29 को जिस वक्त चालान कटा गया, उस दौरान उपनिदेशक की कार घर में खड़ी हुई थी।सर्वेश के मुताबिक वह अयोध्या से लखनऊ कार से ही आए थे। टोल प्लाजा पर लगे कैमरों से भी 26 को उनके लखनऊ में न होने की पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई उनकी कार के नम्बर का दुरुपयोग कर रहा है। इंस्पेक्टर बिजनौर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, २६६ करोड़ से अधिक धनराशि स्वीकृत

लखनऊ (संवाददाता) । प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इन्सेंटिव मनी के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश 177.75 करोड़ एवं मैचिंग राज्यांश 118.50 करोड़ कुल धनराशि 296.25करोड़ की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024–24 के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।उप मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइंस व दिशा निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाए।

रोजगार मेले में १३० युवाओ को मिला जॉब आफर

लखनऊ (संवाददाता) । राजकीय आईटीआई अलीगंज के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि राजकीय आईटीआई, अलीगंज, लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। राज कुमार यादव ने रोजगार मेले को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप इस संस्थान में रोजगार मेलो के माध्यम से युवाओ को रोजगार दिलाने का कार्य किया जा रहा है। हरीश मिश्रा, उप प्रधानाचार्य ने रोजगार मेले का निरीक्षण किया तथा कम्पनियो को अधिक से अधिक प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजित करने के लिए अनुरोध किया। एम ए खाँ ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाली 10 कम्पनियो द्वारा 130 अभ्यर्थियों को जॉब आफर दिया गया। कैम्पस ड्राइव को सफल बनाने के लिए निर्भय कुमार सिंह, कार्यदेशक, मकबूलकादिर एवं जेड रहमान का विशेष सहयोग रहा।

युवा राष्ट्रीय लोकदल की अहम बैठक २३ को

लखनऊ (संवाददाता) । युवा राष्ट्रीय लोकदल की बैठक युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में 23 अगस्त को रालोद के प्रदेश कार्यालय में होगी। युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विपिन द्विवेदी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे तथा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे एवं राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 23 अगस्त को युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पूरे प्रदेश से युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, मंडल, जिला एवं महानगर अध्यक्ष भाग लेने हेतु लखनऊ आ रहे हैं।

विद्युत चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने गई टीम से मारपीट

लखनऊ (संवाददाता)। मलिहाबाद कोतवाली अंतर्गत गढ़ी संजर खां गांव में बुधवार को विद्युत चोरी की शिकायत मे उपभोक्ता के घर पहुंची लेसा टीम से मारपीट की गई। वहीं, उपभोक्ता ने लेसाकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद विद्युत उपकेंद्र के जेई और उपभोक्ता ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मलिहाबाद कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है।मलिहाबाद तहसील में उपकेंद्र में कार्यरत अवर अभियंता त्रिभुवन के मुताबिक, बुधवार को गढ़ी संजर खां गांव में उपभोक्ता सूर्य प्रकाश के घर पर विद्युत चोरी करने के शिकायत मिली थी। इस पर लेसा टीम उपभोक्ता के घर पहुंची गई। उनका आरोप है कि लेसाकर्मियों को देख उपभोक्ता अभद्रता कर सरकारी काम में बाधा डालने लगा। इस दौरान लेसा टीम ने मोबाइल कैमरे से वीडियोग्राफी शुरु कर दी, तो उपभोक्ता ने लेसाकर्मियों का मोबाइल छीन तोड़ दिया। वहीं उपभोक्ता का कहना है कि सुबह करीब छह बजे उसके घर पर कुछ लोग सीढ़ी लगाकर दाखिल हो गए। घर की महिलाएं स्नान कर रही थी, तभी वह लोग वीडियो बनाने लगाने लगे। महिलाओं का शोर सुनकर उनकी नींद खुली तो टीम में मौजूद युवक उस पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाने लगे। लिखित शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उनके घर पर बिजली का मीटर लगा है, कभी भी उसने बिजली चोरी नहीं की है। पीड़ित ने बैगर अनुमति के घर में घुसने और महिलाओं के स्नान करने के दौरान उनका वीडियो बनाने जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों की लिखित शिकायत पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

घट बढ़ रहा राप्ती का जलस्तर, कटान तेज

लखनऊ। नेपाल व पहाड़ों सहित जिले में रुक–रुक कर हो रही बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बुधवार को पांचवें दिन भी खतरे के निशान से ऊपर रहा। नेपाल के कुसुम बैराज से पानी छोड़े जाने से राप्ती बैराज पर जलस्तर कभी 10 सेंटीमीटर ऊपर तो कभी नीचे रहा। ऐसे में कछार के गांवों में कहीं खेत जलमग्न हैं, तो कहीं तेजी से कटान हो रही है। इससे कछारवासी परेशान हैं। जिले में बुधवार को पांचवें दिन भी जमुनहा बैराज पर राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान (127.70 सेंटीमीटर) से ऊपर बना रहा। सुबह चार बजे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर तो शाम को घटकर पांच सेंटीमीटर ऊपर रह गया। जहां बढ़े जलस्तर से राप्ती की लहरें अपने किनारों पर कटान कर रही हैं। वहीं भकला नाले में उफान के कारण उसका पानी जमुनहा के रमवापुर, लाहौर, मुनव्वर गांव, मोंगला, गुरुदत्त पुरवा, हरिहरपुर, बरुआ, पिपरहवा कोठी, बहोरवा अंशिक, भगवानपुर, भगवानपुर भैसाही, झिरझिरवा व भेलागांव आदि गांवों के खेतों को जलमग्न कर रहा है। इससे खेतों में लगी फसल जलभराव से खराब हो रही है।

सम्पादकीय

दूध की सुध

यह मानवीय मूल्यों के पराभव की पराकाष्ठा है कि दूध की जगह रासायनिक पदार्थों से बना जहरीला पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहा है। हकीकत में दूध दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ है, लेकिन भारत में यह संकट बड़ा है। वैसे भारत पिछले दो दशक से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन लगातार पशुधन संख्या में गिरावट के बावजूद दूध से जुड़े आंकड़े संदेह भी पैदा करते हैं। दूध में पानी मिलाने की कथाएं तो सदियों पुरानी हैं। लेकिन हाल के दशकों में उन खबरों ने डराया है, जिनमें कहा गया कि आपराधिक मानसिकता के मुनाफाखोर दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, ग्लुकोज और फॉर्मेलिन आदि मिला रहे हैं। विडंबना देखिये कि सदियों से कहा जाता रहा है कि दूध बलवर्धक व स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है। आज के दौर में खाने–पीने की चीजों में तमाम रासायनिक पदार्थों की मिलावट के बाद एक दूध से उम्मीद होती है कि बच्चे दूध पीकर तंदुरुस्त बनें। लेकिन जब वे रासायनिक पदार्थों से बना दूध पीएंगे तो उनका क्या स्वास्थ्य सुधरेगा? कल्पना कीजिए कि किसी मरीज को डॉक्टर स्वस्थ होने के लिये दूध पीने को कहे और वह नकली दूध पीने से और बीमार पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों पर भी लगातार नकली दूध की चाय बिकने की शिकायतें आती रही हैं। कुछ वर्ष पहले उ.प्र. के एक रेलवे स्टेशन में सफेद रंग से बने दूध की चाय बिकने की शिकायत सामने आई थी। लेकिन इसके बावजूद इस मिलावट पर अंकुश लगाने के लिये हितधारकों की तरफ से कोई गंभीर प्रयास होते नजर नहीं आते। यह दुखद ही है कि हर घर में प्रयुक्त होने वाले दूध की गुणवत्ता में भारी गिरावट के बाद भी शासन–प्रशासन की दृष्टि में यह गंभीर मुद्दा नहीं है। न ही राजनीतिक दल ही इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करते हैं। जिसकी वजह से मिलावट करने वालों के हौसले बुलंद हैं। बहरहाल, आज यदि समाज में सेहत के लिये घातक रासायनिक पदार्थों से बना नकली दूध धड़ल्ले से बिक रहा है तो स्वाभाविक प्रश्न है कि जिन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का जिम्मा है, क्या वे ईमानदारी से अपने दायित्वों को निभा रहे हैं? दरअसल, इन मलाईदार पदों पर नियुक्ति में जिस तरह धनबल व राजनीतिक बल चलता है, वह पद कालांतर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी में बदल जाता है। तभी दिवाली आदि त्योहारों में मिठाई के लिये बाजार में दूध, मावे और पनीर की बाढ़ आ जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति वर्ष के शेष महीनों में नहीं होती। सवाल स्वाभाविक है कि दिवाली व अन्य त्योहारों के समय दूध व उसके उत्पादों से जो बाजार भर जाता है, साल के शेष महीनों में वह दूध आदि क्यों नजर नहीं आता? इस खेल की तह तक जाने की जरूरत है। वहीं क्या उपभोक्ताओं को मिलावटी दूध से स्वास्थ्य को पैदा होने वाले खतरों के प्रति जागरूक किया जाता है? विडंबना देखिए कि पंजाब, जहां प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है, वह मिलावटी दूध के दाग को धोने के लिये संघर्षरत है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में एकत्र किए गए दूध व दूध से बने उत्पादों के लगभग 18 प्रतिशत नमूने फेल हुए हैं। वहीं दूध–दही के खाने के लिये प्रसिद्ध हरियाणा में भी 28 फीसदी नमूने मानक कसौटी पर खरे नहीं उतरे । जैसे–जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है नमूने भरने, तलाशी लेने और मिलावट करने वालों की धरपकड़ की रस्मी कार्रवाई तेज हो जाएगी। लेकिन अब तक सुना नहीं गया कि किसी दोषी को कोई बड़ी सजा मिली हो। दरअसल, इन मामलों में कड़ी सजा न मिलने से मिलावट करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं। उन्हें पता है कि आखिरकार येन–केन–प्रकारेण वे बच ही जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम उपभोक्ता के लिये दूध में मिलावट की पहचान करने वाली किट बाजार में सहजता से उपलब्ध हों। इस किट को किफायती, उपयोगकर्ता के अनुकूल तथा सटीक जानकारी देने वाला बनाया जाए। खाद्य सुरक्षा एजेंसियों को उत्पादों की जांच, नमूने लेने तथा दोषी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

कड़े कानून नहीं, सोच बदलने से थमेगी यौन हिंसा

विश्वनाथ सचदेव

कोलकाता के एक अस्पताल में हुए जघन्य कांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। पश्चिम बंगाल की पुलिस को अक्षम ठहराकर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतरू संज्ञान लिया है। उधर देशभर के डॉक्टरों का विरोध–प्रदर्शन जारी है। वे सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। इस मांग के औचित्य पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह सारे मामले को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है उसे देखते हुए न्याय की मांग करने वालों के इरादे पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। निस्संदेह मामला बहुत गंभीर है और बलात्कार का यह मुद्दा कानून–व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की अक्षमता को भी उजागर करने वाला है। उम्मीद ही की जा सकती है कि अपराधी शीघ्र ही पकड़े जाएंगे और मरीजों को अस्पतालों में समुचित चिकित्सा मिलेगी, डॉक्टर को बिना डरे अपना काम करने का माहौल मिलेगा। मरीजों और डॉक्टरों के प्रति हमारी व्यवस्था को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। इस मामले में न्याय मांगने वाले अपराधी या अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड, फांसी, दिये जाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपराधी को ऐसा दंड मिलना ही चाहिए जो शेष समाज को यह चेतावनी देने वाला हो कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी नृशंसता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा का एक परिणाम यह भी निकल रहा है कि अपराधी सबूत को मिटाने के चक्कर में बलात्कार के बाद हत्या का मार्ग अपना रहे हैं। दिल्ली की 'निर्भया' से लेकर कोलकाता की 'निर्भया' तक की यह शृंखला यही बता रही है कि मनुष्यता के खिलाफ किए जाने वाले इस अपराधदृ बलात्कार के दोषी सिर्फ कड़े कानूनों से नहीं डर रहे हैं। जिस दिन कोलकाता के एक अस्पताल में यह जघन्य कांड हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी बलात्कार–हत्या की घटनाएं सामने आने लगीं। यह स्थिति निश्चित रूप से भयावह है। स्पष्ट दिख रहा है कि अपराधियों को कानून–व्यवस्था का डर नहीं रहा, कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि कानून उनकी मनमानी को रोकने में सक्षम नहीं है। स्थिति की गंभीरता और भयावहता को कुछ आंकड़े उजागर कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की गणना के अनुसार हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बलात्कार चौथा सबसे गंभीर अपराध है। प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में देश में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज हुए थे, अर्थातद्द रोज 86 मामले यानी हर घंटे चार। ज्ञातव्य है

कि इसके पहले के दो वर्षों में यह संख्या कम थीदृ सनद्द 2020 में 28,046 मामले और सन 2019 में 32,033 मामले। यह आंकड़े तो उन अपराधों के हैं, जो थानों में दर्ज हुए। हकीकत यह है कि आज हमारे देश में कम से कम इतने ही मामले थानों में दर्ज नहीं होते! यह मानकर कि अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी, पीड़ित पक्ष 'पुलिस के चक्कर' में पड़ते ही नहीं। साथ ही बलात्कार की शिकार महिलाएं और उनके परिवार वाले समाज के 'डर' से भी पुलिस के पास जाने में हिचकिचाते हैं। बलात्कार स्त्री पर किया गया जघन्य अपराध है, लेकिन हमारे यहां बलात्कार की शिकार महिलाओं को ही संदेह और नीची दृष्टि से देखा जाता है! आज मुख्य सवाल इस दृष्टि के बदलने का है। और यह काम सिर्फ कड़े कानून से नहीं होगा। बलात्कार करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यह सब चाहते हैं, लेकिन यह बात कोई नहीं समझना चाहता कि आवश्यकता उस दृष्टि को बदलने की है जो महिला को एक वस्तु मात्र समझती है। अपराधी यह दृष्टि भी है। सज़ा इसे भी मिलनी चाहिएदृ इस दृष्टि को बदलने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से कहीं आगे हैं वे। इसके बावजूद उन्हें कमजोर समझा–कहा जाता है। यह उसी सोच का परिणाम है जो अबला जीवन को 'आंचल में दूध और पलकों में पानी' से आगे नहीं देखना चाहता। इस सोच को बदलने की जरूरत है। नारी को पुरुष के सहारे की नहीं, बराबरी के सहयोग की आवश्यकता है और पुरुष को यह समझना होगा कि वह भी नारी के सहयोग के बिना अधूरा है। जितनी आवश्यकता नारी को पुरुष की है, उतनी ही आवश्यकता पुरुष को भी नारी की है। यह काम कानून को कड़ा बनाने से नहीं, समाज की सोच को बदलने से होगा। हम देख रहे हैं कि इस संदर्भ में कानून को कड़ा बनाना अपराध और अधिक जघन्य बना रहा है, उम्मीद करनी चाहिए कि कानून अपना काम करेगा और समाज की सोच भी बदलेगी। इस दिशा में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन, आज आवश्यकता उस सोच को भी बदलने की है जो हमारे राजनेताओं को हर स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने का लालच देती है। यह सही है कि बलात्कार का यह वीभत्स कांड कोलकाता का है और पश्चिम बंगाल की सरकार का दायित्व है कि वह इस दिशा में ठोस कार्रवाई करे। लेकिन बलात्कार की समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। कोलकाता में तो बलात्कार के सबसे कम मामले दर्ज होते हैं। इस संदर्भ में राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ताज़ा उदाहरण यह भी बताता है कि कोलकाता के इस कांड के दूसरे–तीसरे दिन ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटीं। इस बारे में हमारे राजनीतिक दलों ने जिस तरह का रवैया अपनाया है उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। बंगाल में भाजपा का मुकाबला ममता की तृणमूल–कांग्रेस पार्टी से है इसलिए भाजपा वहां सरकार बदलने की मांग कर रही है। यह ग़लत प्रवृत्ति है। हर बात को राजनीतिक नफे–नुकसान की दृष्टि से देखकर हम आने वाले कल का विकसित भारत नहीं बना पायेंगे। यह बात हमारे राजनेताओं को समझनी होगी। तभी समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा, तभी हमारा भारत विकसित होगा। बलात्कार के किसी कांड को राजनीति का हथियार बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। बलात्कार और बलात्कारियों को किसी भी दृष्टि से छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि ऐसा अपराध करने वाला ही नहीं, ऐसे अपराध को सहने वाला समाज भी दोषी होता है।

सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव समर्थन को प्रतिबद्ध : कपिलदेव

लखनऊ (संवाददाता) । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व उद्यमिता दिवस के उपलक्ष्य में स्वावलम्बी भारत अभियान के अंतर्गत भव्य उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराकर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 21 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता प्रोत्साहन से संबंधित गतिविधियों काआयोजन होगा। इस अभियान की शुरुआत लखनऊ के अलीगंज स्थित कौशल विकास मिशन के सभागार में की गई, जहां प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार भी इस दिशा में हरसंभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मिशन निदेशक अभिषेक सिंह ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज के दौर में उद्यमिता न केवल रोजगार सृजन का साधन है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिनके माध्यम से युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।विशिष्ट अतिथियों में रश्मि सिंह, आईएएस, आरएसएस के विशेष संपर्क प्रमुख प्रशांत भाटिया और स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्र संयोजक अनुपम श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने वक्तव्यों में स्वावलम्बी भारत अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

इस सम्मेलन के दौरान युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में लोन प्रदान करने की योजना पर भी चर्चा हुई। बैंक ऑफ इंडिया ने इस पहल में लीड बैंक की भूमिका निभाने का वादा किया। बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर ने बताया कि बैंक इस दिशा में पूरी तरह से सहयोग करेगा और युवाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि वे अपने उद्यम स्थापित कर सकें और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।इस कार्यक्रम में उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया।

यूपी के 247 पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का होगा सर्वे : जयवीर

विदेशी पर्यटको के मामले में यूपी को बनाना है देश में अव्वल

लखनऊ (संवाददाता) । उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की गणना करने एवं उनके अनुभव को साझा करने के लिए प्रदेश के 247 स्थलों पर आने वाले पर्यटकों का एक वर्ष तक सर्वे कराया जाएगा। यह स्थल प्रत्येक जिले में स्थित हैं, जहां एक सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक सर्वे होगा। इसके लिए पर्यवेक्षक लगाये जायेंगे। इन पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न बारीकियों की जानकारी देने के लिए बुधवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 200 से अधिक सर्वेयर्स को प्रशिक्षित किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के अलावा इन सर्वेयर्स को चारबाग रेलवे स्टेशन और बीकेटी स्थित चंद्रिका देवी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण भी कराया गया। यूपी पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास करने वाला राज्य है। घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी देश में अव्वल है। विदेश से आने वाले पर्यटकों के मामले में भी यह उपलब्धि हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन स्थल और पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशी

पर्यटकों के मामले में भी देश में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए पर्यटन स्थलों को नये सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। सरकार पर्यटकों को और अच्छी सुविधाएं दे सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, नियोजन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक जिले का सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एआईआईएलएसजी को कार्यदायी संस्था चुना गया है। सर्वे के द्वितीय चरण हेतु प्रदेश में 247 पर्यटन स्थलों को चिह्नित किया गया है। द्वितीय चरण के सर्वे हेतु एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एआईआईएलएसजी के टेक्निकल डायरेक्टर पश्चिम तिवारी ने सर्वेयर्स को सर्वे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर्वे के जो नियम बनाए गए है उसका हर हाल में पालन करें। विशेषज्ञों ने भी सरवेयर्स का मार्गदर्शन किया।प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम के नेतृत्व में सर्वे का प्रथम चरण जून माह में पूरा कराया गया। पर्यटन स्थलों के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे एवं अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित मार्ग के प्रवेश–निकास स्थल, होटल्स, रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस, होम–स्टे, पेईंग गेस्ट एवं ढाबे इत्यादि, विश्राम स्थलों में आने वाले पर्यटकों की गणना की गई है। निदेशक पर्यटन प्रखर मिश्रा ने बताया कि सर्वे का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला कि पर्यटकों की गणना करना, दूसरा उद्देश्य है कि वह कितना खर्च कर रहा है ताकि हमें पता चल सके कि पर्यटन क्षेत्र से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और संभावनाएं क्या है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सर्वेक्षण अति महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए संवेदनशीलता के साथ किया जाना है। प्रशिक्षण के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर अमित कुमार, विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया, उपनिदेशक पूजा अग्निहोत्री, नियोजन विभाग के उपनिदेशक नवीन चतुर्वेदी समेत अधिकारी मौजूद रहे।

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने काला फीता बांध कर शुरू किया विरोध

लखनऊ (संवाददाता)। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में कार्यरत करीब 20 हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। संविदा पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (एनएचएम) ऑनलाइन लगने वाली हाजिरी से नाराज हैं। वह अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं। सीएचओ ने आज से काम बंद कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। दरअसल, अगस्त माह में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ((एनएचएम) ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर उपस्थिति में सुधार की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि सभी सीएचओ को तैनाती स्थल यानी की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रोजाना दो बार अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर हाजिरी लगानी होगी। उसके बाद ही वह फील्ड के कार्य पर जा सकेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन आफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर एएमएस पर उपस्थिति में सुधार की मांग की गई थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई, तो आंदोलन ही एक मात्र रास्ता बचता है। ऐसे में सीएचओ ने कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए एम्स को उक्त प्रणाली स्वास्थ्य विभाग के सभी नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग, अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो न कि केवल सीएचओ या संविदाकर्मी पर। इसके अलावा भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सीएचओ का कैडर निर्माण कर, 6 वर्ष की सेवा दे चुके सीएचओ को नियमित किया जाए। अन्य राज्यों की तरह सीएचओ का वेतन उत्तर प्रदेश में भी 2500015000 किया जाए और पीबीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय, मणिपुर में एनएचएम के तहत सीएचओ को 4800 ग्रेड पे अनुरूप वेतन का निर्धारण और महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स लागू करने से पहले अन्य विभागों या सरकारी कर्मियों की भाँति सीएचओ के लिए वर्ष में 30 अर्जित अवकाश (इंतदमक स्मंअम) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए की भविष्यवाणी

लखनऊ। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत इन जिलों में इलाकों समेत 15 से ज्यादा जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को बस्ती में 29.7 मिमी, वाराणसी में 26.8 मिमी, लखनऊ

भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी पूर्वी, दक्षिणी और तराई इलाकों में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बृहस्पतिवार को यूपी के दक्षिणी व पूर्वी में 14.9 मिमी, फुरसतगंज में 13.7 मिमी और हरदोई में10.2 मिमी बारिश दर्ज हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार को उप्र के दक्षिणी हिस्सों सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश के संकेत हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकतर जगहों पर अगले तीन चार दिन रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो बुधवार को प्रदेश में मेरठ में सबसे अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

वहीं प्रयागराज में 34.9 डिग्री और उरई में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चुर्क में सबसे कम 23.4 डिग्री सेल्सियस तो गाजीपुर में 24 डिग्री और इटावा में 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

इन इलाकों में है भारी बारिश की चेतावनी–

मौसम विभाग की ओर से बृहस्पतिवार के लिए बांदा, चित्रकूट, कौशांबी,प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, श्रावस्ती, बहराइच, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

निर्यात और निवेश के समक्ष नई चुनौतियां

जयंतीलाल भंडारी

हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत से वस्तुओं का निर्यात जुलाई 2024 में सालाना आधार पर 1.2 प्रतिशत घटकर 33.98 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने में निर्यात का मूल्य 34.39 अरब डॉलर था। जहां इस समय भारतीय निर्यातक बांग्लादेश के सियासी हालात को लेकर चिंतित हैं, वहीं वे चीन को किए जा रहे निर्यात में कमी से भी चिंतित हैं। साथ ही निर्यातकों को विदेशी बाजारों में कमजोर मांग और व्यापार में अन्य बाधाओं से जूझना पड़ रहा है। पिछले दिनों भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एग्जिम बैंक) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के वस्तु निर्यात में वृद्धि जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही में घटकर 4 फीसदी रह सकती है। कहा गया है कि इस समय वैश्विक परिदृश्य विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं से प्रभावित होने के कारण भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निस्संदेह, इन दिनों बांग्लादेश के राजनीतिक संकट, भयावह होते रूस–युक्रेन युद्ध, इस्राइल–ईरान संघर्ष और अमेरिका व जापान सहित दुनिया के कई देशों में मंदी की लहर के कारण भारत से निर्यात की रफ्तार और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की चुनौतियां बढ़ गई हैं। एक अगस्त से सरकार ने चीन सहित सीमावर्ती देशों से भारत में विनिर्माण परियोजनाओं से जुड़े टेक्नीशियनों के लिए नई वीजा व्यवस्था लागू कर दी है। वर्ष 2024–25 के आम बजट में भी इस परिप्रेक्ष्य में कारगर रणनीतियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही वाणिज्य विभाग निर्यात प्रोत्साहन की दो महत्वपूर्ण योजनाओं को उनकी समाप्ति तिथि से आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक अस्थिरता से भारत–बांग्लादेश व्यापार पर नया संकट खड़ा हो गया है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा बांग्लादेश भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। पिछले वर्ष 2023–24 में भारत ने बांग्लादेश को 11 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया है।चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून, 2024 की पहली तिमाही में जहां निर्यात धीमी रफ्तार से बढ़े हैं, वहीं आयात की रफ्तार अधिक रहने से विदेश व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। इन तीन महीनों में कुल निर्यात 200.33 अरब डॉलर मूल्य के रहे हैं, जिसमें वस्तु निर्यात 109.96 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 90.37 अरब डॉलर मूल्य के हैं। जबकि कुल आयात 222.90 अरब डॉलर मूल्य के हैं। जिसमें वस्तु आयात 172.23 अरब डॉलर और सेवा आयात 50.67 अरब डॉलर मूल्य के हैं। चूंकि इस वित्त वर्ष में भारत द्वारा कुल निर्यात का लक्ष्य पिछले वर्ष के कुल 776 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात से भी कुछ अधिक 800 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है।यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक सुस्ती व बड़े देशों के बीच युद्ध की तनातनी से देश के एफडीआई परिदृश्य पर भी चुनौतियां बढ़ी हैं। भारत में एफडीआई का प्रवाह 2023–24 में 3.49 प्रतिशत घटकर 44.42 अरब डॉलर रह गया। इसका कारण सेवा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, ऑटो और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश

का कम रहना है।

2022–23 के दौरान एफडीआई का प्रवाह 46.03 अरब डॉलर था। पिछले वर्ष कुल एफडीआई जिसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं– एक प्रतिशत घटकर 70.95 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2022–23 में यह 71.35 अरब अमेरिकी डॉलर था।एक, वर्ष 2024–25 के बजट के तहत निर्यात बढ़ाने और एफडीआई आकर्षित करने के लिए सुनिश्चित किए गए अभूतपूर्व बजट आवंटनों का शुरुआत से ही कारगर उपयोग किया जाए। दो, सेवा निर्यात को हरसंभव तरीके से बढ़ाया जाए और सेवा क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित की जाए। तीन, निर्यातकों को शुल्क के अलावा आने वाली बाधाओं (नॉन–टैरिफ बैरियर) से राहत दी जाए तथा एफडीआई की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए तथा चार, नए संभावित निर्यात बाजार तलाशे जाएं और एफडीआई के नए वैश्विक निवेशक खोजे जाएं। इसमें कोई दोमत नहीं है कि एक अगस्त से लागू की गई व्यापार वीजा की नई व्यवस्था निर्यात व निवेश बढ़ाने में लाभप्रद होगी।वर्ष 2024–25 के बजट में वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर सशक्त बनाया है। साथ ही इस सेक्टर के आयात में कमी के मद्देनजर प्रावधान किए गए हैं। नए बजट से सरकार ने जरूरी इकोसिस्टम को तैयार कर ठंडे पड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूंकने और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम को मजबूती देने के प्रावधान किए हैं। नए बजट में मशीनरी की खरीदारी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लांच की गई है।

इस स्कीम के तहत सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा जिसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी होगी। वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के इस्तेमाल से जुड़े नियम सरल बनाए गए हैं, जो व्यापार नीति के लिहाज से सकारात्मक उपाय हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव मोदी सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा

सुशील कुट्टी

जम्मू–कश्मीर में आदर्श आचार संहिता लागू है साथ ही भारत के संविधान की धारा 370 भी निरस्त है। फारूक अब्दल्ला और महबूबा मुफ्ती को कोई शिकायत नहीं है। दोनों खुश हैं कि आखिरकार 90 सदस्यीय जम्मू–कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अगस्त को नयी दिल्ली में इस फैसले की घोषणा की और श्रीनगर में इसके असर को महसूस किया। बेशक, सभी भाजपा नेताओं की तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए मोदी को प्रशंसा मिलेगी। लोग भूल जाते हैं कि मोदी धारा 370 को हटाने के लिए मुख्य प्रस्तावक थे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके कारण जम्मू–कश्मीर विभाजित हुआ और चुनाव 10 साल बाद पहली बार हो रहे हैं।मोदी के प्रतिनिधि 2019 के मध्य से जम्मू–कश्मीर पर शासन कर रहे हैं और यह एक खुशहाल शासन नहीं रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनेता फंसे हुए हैं और आम लोग दुष्प्रचार से घिरे हुए हैं। क्या कश्मीरी इन चुनावों पर भरोसा करते हैं? कश्मीरियों का एक बड़ा हिस्सा इंतजार ही इंतजार कर रहा है ... और वे भी मैदानी इलाकों के मुसलमानों से कोई अलग नहीं होंगे। कम से कम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सीधे तौर पर कहा है, फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कभी भी स्वयं को पाक–साफ प्रस्तुत नहीं कर सकते। मोदी और शाह अब मानते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला और मुफ्ती को काबू में कर लिया है। जम्मू–कश्मीर में ऐसी गलतफहमियां आम बात रही हैं। एक बार मोदी और शाह को दिल्ली से भगा दिया जाये, जिसके लिए भाजपा को 2029 में हराना होगा, धारा 370 फिर से कानून की किताब में शामिल हो जायेगी और जम्मू–कश्मीर और लद्दाख फिर से एक हो जायेंगे। तब तक हर छोटी–छोटी बात मायने रखती है और जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव का स्वागत है। मोदी और शाह अल्पकालिक के लिए सभी प्रशंसाएं ले सकते हैंय दीर्घकालिक उन्हें पसंद नहीं आयेगा। भाजपा को पहले से ही अपने आसन्न विनाश की भनक लग चुकी है। एक और धक्का और पूरी इमारत झुक और गिर जायेगी। जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी शुरुआत 18 सितंबर से होगी। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने के एक दिन बाद तारीखों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास पीएम मोदी की एक राष्ट्र–एक चुनाव की मांग पर कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने मोदी से सवाल पूछने का काम मीडिया पर छोड़ दिया। जम्मू–कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग श्समावेशी और सुलभ चुनावों के लिए प्रतिबद्ध है।चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और तीसरा और अंतिम चरण 1 अक्टूबर, 2024 को होगा, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से एक दिन पहले है, जब केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 87 लाख मतदाता अपने वोट डाल चुके होंगे– यह होगा लोकतंत्र की जीत! फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सीईसी राजीव कुमार को जितना धन्यवाद दें, कम है। दोनों ही वंश एक दशक से अधिक समय से सत्ता से बाहर हैं।पिछली बार जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव मई 2014 में हुए थे। तब से जम्मू–कश्मीर के मतदाता केंद्र शासित प्रदेश के अधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जम्मू–कश्मीर के लोग खुश हैं। सीईसी राजीव कुमार भी खुश हैं। कुमार कहते हैं कि 10 सालों में जम्मू–कश्मीर में हालात काफी बेहतर हुए हैं, खास तौर पर धारा 370 के निरस्त होने के बाद। कुमार कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों ने लोकतंत्र की परतों को मजबूत किया है और जम्मू–कश्मीर के लोग उत्साह से भरे हुए हैं। राजीव कुमार ने भाजपा नेता की तरह बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें इस बात का सुबूत हैं कि लोग न केवल बदलाव चाहते थे बल्कि उस बदलाव का हिस्सा बनकर अपनी आवाज भी उठाना चाहते थे। राजीव कुमार ने जो संदेश दिया वह यह था कि जम्मू–कश्मीर के लोगों ने बुलेट के बजाय बैलेट को चुना। कुमार दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं और वे कई चुनाव आयुक्तों से अलग नहीं हैं जो पवन चक्कियों पर झुकते हैं। मतदाताओं की उच्च भागीदारी की उम्मीद है। कुमार पूर्ण निष्पक्षता और समान अवसर का भी वायदा करते हैं। इसके बावजूद, ये चुनाव सुरक्षा बलों पर अभूतपूर्व आतंकवादी हमलों की छाया में आयोजित किये जायेंगे। ऐसा माना जाता है कि जम्मू के वन क्षेत्रों में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के कमांडो हैं। इनमें से कुछ को निष्प्रभावी कर दिया गया है, लेकिन सभी को नहीं। राजनेताओं को सुरक्षा प्रदान की जायेगी, लेकिन क्या मतदाता बंदूकों की छाया में अधिकाधिक संख्या में मतदान करेंगे?

विधायक सहित भाजपा नेताओं ने निकाली हर घर तिरंगा यात्राः शहीद स्थल छावनी पर दिया संदेश

संवाददाता–बस्ती। सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा हरैया डाक बंगले से प्रारंभ होकर शहीद स्थल छावनी पर समाप्त हुई जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल, हरैया विधायक अजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।

शहीद स्थल छावनी पहुंचने के बाद प्रदेश महामंत्री, विधायक और जिलाध्यक्ष ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा हमारी पहचान और हम सभी भारतवासी का गौरव है। तिरंगा को देखकर हर भारतवासी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। विधायक अजय सिंह ने कहा कि हम देशवासियों को देशप्रेम और वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक आम जनमानस में देश के उत्सव के रूप में स्थान बना चुका है।

तिरंगा यात्रा के दौरान भानु प्रकाश मिश्रा, अमृत कुमार वर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित गुप्ता, मण्डल अध्यक्ष हरैया, मण्डल अध्यक्ष विक्रमजोत सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी शामिल रहे।

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण का निर्देश

संवाददाता–बस्ती। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुआ। उन्होने उद्यमियों की समस्याओं को एक–एक करके गम्भीरतपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होने अधिकारियों को निर्देषित किया कि उद्यमियों की षिकायत को समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जायें। उन्होने निवेशमित्र पोर्टल पर विभागवार लम्बित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने ऋण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण सहायता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, औद्योगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विचार की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 में हस्ताक्षरित एमओयू के विभागवार प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। उन्होने बताया कि वर्तमान माह तक 296 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके है, जिसमें 14434.30 करोड़ का पूँजीनिवेश एवं 19945 का रोजगार प्रस्तावित है।

जिला स्तरीय वाणिज्य बन्धु समिति की बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी रवीष गुप्ता ने व्यापारी संगठनों के पदाधिकारीगणों की उक्त मांगों के दृष्टिगत संबधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण हेतु निर्देषित किया। बैठक में व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पेयजल, जलजमाव, पाण्डेय बाजार रेलवे कासिंग पर जाम के दृष्टिगत ओवरब्रिज बनाये जाने के संबध में प्रतिवेदन दिया गया।

बैठक में सीडीओ जयदेव सी.एस. , एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा, एलडीएम आर.एन. मौर्या, अपर मुख्य अधिकारी विनय वर्मा, महासचिव चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्ड0 एच0सी0शुक्ला एवं अध्यक्ष अषोक सिंह, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट एसोसीएशन अनिल सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं उद्यमीगण तथा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, सदस्य रेलवे सलाहाकार बोर्ड तथा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ०प्र० व अन्य व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

जीआईएस आधारित कर निर्धारण में मनमानी बर्दाश्त नहीं

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्य संवाददाता जीआईएस आधारित सम्पत्तिकर निर्धारण के खिलाफ गोरखपुर नगर निगम के समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को सपा पार्षद दल नेता अशोक यादव की अगुवाई में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को ज्ञापन देकर जीआईएस सर्वेक्षण आधारित बिल का वितरण तत्काल रोकने की मांग की। चेताया कि निगम की मनमानी नहीं रुकी तो हस्ताक्षर अभियान लेकर वार्डो में जनता के बीच जाएंगे। सपा पार्षद दल नेता अशोक यादव एवं जिलाउल इस्लाम ने आरोप लगाया कि नगर निगम की सभी बैठकों में जीआईएस सर्वेक्षण आधारित सम्पत्तिकर के निर्धारण पर हर बार भवन स्वामियों की समस्याओं को उठाया गया। लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि सर्वेक्षण करने वाली कंपनी ने भवन स्वामियों का डाटा गलत दर्शाया। भवन स्वामियों को भेजे गए जीआईएस सर्वेक्षण आधारित नोटिस में सड़क की चौड़ाई ज्यादा दिखाई जा रही है जबकि मौके पर उतनी नहीं है। यही नहीं, भवन कर निर्धारण में कारपेट क्षेत्रफल पूरे भवन खंड से लिया जा रहा है, यह नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार पूर्णतया गलत है। यही नहीं, सर्वेक्षण में जिन क्षेत्रों में वाटर लाइन, सीवर लाइन नहीं पड़ी है, या सेवा नहीं दे रही है, सम्पत्तिकर में उन्हें भी शामिल किया गया है। सपा पार्षदों ने चेताया कि नगर निगम इस मनमाने कर निर्धारण पर लगाम नहीं लगाती तो जनान्दोलन के लिए मजबूर होंगे। प्रथम चरण में सभी वार्डों में हस्ताक्षर अभियान चलेगा, उसके बाद जनता के साथ सड़क पर आएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में अशोक यादव, जियाउल इस्लाम, शहाब अंसारी, रमेश यादव, जुबेर अहमद, उज्जैर अहमद, बिजेंदर अग्रहरि, वजीउल्लाह अंसारी, अभिषेक पासवान ,चंद भान प्रजापति ,दिलशाद आलम, विक्की मिश्रा, नूर मोहम्मद, दिनेश गुप्ता ,दानिश मुस्तफा, आयशा खातून, मनोज त्रिपाठी ,शाहिद अख्तर, सबिया खातून, इरशाद अहमद ,जावेद खान, इश्तियाक बबलू, उमाशंकर जायसवाल, मिनाजुद्दीन अंसारी, नफीस अहमद अंसारी, सिंहासन सिंह यादव समेत अन्य उपस्थित रहे।

कार्य बहिष्कार कर आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर भरी हुंकार

संवाददाता–महराजगंज। प्रोत्साहन राशन, 10 लाख का बीमा व मृतक आश्रितों को नौकरी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर सोमवार को आशा कार्यकर्त्रियों एवं संगिनियों ने कार्य बहिष्कार कर अपनी आवाज बुलंद की। मुख्यालय पर धरना–प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को भेजा। धरनास्थल पर वक्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं को जन–जन तक पहुचाने में कार्यकर्त्रियों व संगिनियों का विशेष योगदान रहता है। आशाओं के प्रयास से ही कोरोना जैसी महामारी पर विजय हासिल हुई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहता है। पीएमवीवाई लाभार्थियों का फार्म भरवाने पर पहले आशा कार्यकत्री को प्रोत्साहन राशि 100 रुपया मिलता था। अब प्रोत्साहन राशि 250 रुपया होने पर फार्म भरने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ियों को दे दिया गया जो आशाओं के साथ सौतेला व्यवहार है। आशा कार्यकत्रीध्आशा संगिनी और लाभार्थी का भुगतान भी पिछले दो वर्षों से लंबित है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में आशाओं ने पीएमवीवाई की पिछले दो साल की बकाया प्रोत्साहन राशि का जल्द भुगतान करने। प्रोत्साहन राशि 250 रुपये होने पर आंगनबाड़ी को फार्म भरने की जिम्मेदारी वापस कराना, आशा कार्यकत्रीध्आशा संगिनी को राज्य कर्मचारी का दर्जा और एक निश्वित मानदेय 18000 रुपया प्रतिमाह देने की मांग की गई है। इसके अलावा आशाओं को दुर्घटना बीमा 10 लाख करने के साथ बीमा प्रमाण पत्र देने, आशा कार्यकत्रीध्आशा संगिनी की मृत्यु के बाद आश्रितों को नौकरी देने की मांग की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष जमीरून निशा, निर्मला देवी, बबिता विश्वास, संध्या, संजू, मीना, पूनम, मीरा, निर्मला पाल, गीता, नीलम, विनीता शर्मा, रेखा यादव, कंचन लता, ममता, राजेश्वरी, फूलकुमारी, अनीता, ऊषा, रीता, संगीता, प्रतिभा, कुसुम , मेवाती, रीता, कालिंदी, मंजू, सरिता, सोना, सुनीता, चंद्रावती, जगवंता आदि आशाएं मौजूद रहीं।

मेडिकल कालेज के रेजिडेंट डाक्टरों ने किया प्रदर्शन, ओपीडी

संवाददाता–गोरखपुर। कोलकाता में रेजीडेंट डॉक्टर की हत्या के विरोध की आंच बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई है। सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रेजीडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों के इस प्रदर्शन से ओपीडी प्रभावित हुई है। कुछ विभागों में मरीज बैरंग लौट गए। इस दौरान डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस मामले में आंदोलन का ऐलान किया है। इसी क्रम में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर आंदोलन पर उतर गए। सोमवार को सुबह करीब 11रू00 बजे जूनियर डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। डॉक्टर एक–एक विभाग में जाकर साथियों को जुटाए। इसके बाद बाबा राघव दास की प्रतिमा के पास पहुंचे। वहां से प्रोटेस्ट मार्च निकाला। डॉक्टर इस दौरान डॉक्टर ने कहा कि यह दर्दनाक घटना है। इससे पूरा देश स्तब्ध है। चिकित्सक की ड्यूटी इमरजेंसी होती है। वह मरीज की जान बचाने के लिए रात में ड्यूटी करता है। उसकी सुरक्षा जरूरी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके भी इंतजाम होने चाहिए।

प्रभारी प्राचार्य डॉ पवन प्रधान ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इससे ओपीडी पर आंशिक असर पड़ा है। ज्यादातर विभागों में ओपीडी संचालित हुई है।

एआरटीओ ऑफिस में अफसरों का छापा, एक संदिग्ध गिरफ्तार

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। हाल के दिनों में बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी के परिवहन कार्यालयों में बाहरी व्यक्ति विभागीय फाइल इधर उधर करते मिले थे। वहीं गैर विभागीय लोगों से जांच कराकर वसूली का मामला पकड़ा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों का छापामार निरीक्षण करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन आए दिन कार्यालयों का निरीक्षण करा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अपर जिलाधिकारी डॉ सदानंद गुप्त ने अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय, सदर क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मौर्य और अकबरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बीबी सिंह के साथ सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापा मारा। एक साथ कई अफसरों के छापा मारने से एआरटीओ कार्यालय में खलबली मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अफसरों ने सभी से उनके पटल के बारे में पूछताछ की। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। माकूल जवाब न दे पाने के चलते युवक को अकबरपुर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। युवक नगर के इंद्रलोक कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। अफसरों ने सभी पटल का बारीकी से निरीक्षण किया। पत्रावलियों के रखरखाव को देखा। इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह यादव को कड़े निर्देश दिए। पटल पर सूचना सही व स्पष्ट शब्दों में लिखने और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश न देने का कड़ा निर्देश अपर जिलाधिकारी ने दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निरीक्षण शासन के निर्देश पर किया जा रहा है।

पूर्व विधायक संजय प्रताप ने किया खाद्यान्न माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

संवाददाता–बस्ती । रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सरकारी क्रय केन्द्रो पर किये गये फर्जी खरीद के मामलों की उच्च स्तरीय कराने का आग्रह किया है।

पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि विधानसभा क्षेत्र 309 रुधौली के तहसील रुधौली क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम सभा मुगरहा, पुरैना, मैनी, पैड़ा आदि गांव के आम जनमानस द्वारा संज्ञान में लाया गया कि ग्राम मुगरहा के श्रीमती अफजल पत्नी अकबर के द्वारा कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, बस्ती के नोटिस पत्रांक संख्या 2023 के द्वारा आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ कार्यालय पत्र संख्या 2718 परिवार कल्याण योजना 2022 दिनांक 10/05/2024 के द्वारा प्रचलित राशन कार्डों की एन.आई.सी. से प्राप्त सूची उपलब्ध कराया गया । इस क्रम में गरीब जनता के राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है, जिसकी नोटिस जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा भेजा जा चुका है। सूत्रो द्वारा यह जानकारी हुई है, कि खाद्य माफियाओं द्वारा क्रय केन्द्रो की जिम्मेदार एवं मिलर की मिलीभगत से ग्रामीणो का आधार कार्ड मांगकर तहसील प्रशासन, लेखपाल कानूनगो आदि के द्वारा जिनके नाम से जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है उनके नाम से पांच एकड़ से अधिक फर्जी खतौनी बनाकर तहसील प्रशासन द्वारा प्रमाणित कर खाद्यान माफियाओं, क्रय केन्द्रो, मिलरो द्वारा फर्जीवाड़ा करके खाद्य विभाग को खरीद का डाटा उपलब्ध कराया गया है। खाद्यान माफियाओं द्वारा आधार कार्ड, धारको के घर जाकर उनके खातो में आया हुये पैसे को गलत खाता बताकर सही करने के बहाने अंगूठा और ओटीपी मांगकर पैसा निकाल लिया गया है।

पूर्व विधायक संजय ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि तहसील प्रशासन एवं (खाद्य एवं रसद विभाग) जिला सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बस्ती द्वारा निर्धारित क्रय केन्द्रो के जिम्मेदारो एवं खाद्यान्न माफियाओं की मिली भगत से गरीब जनता के आधार कार्ड पर भुगतान कर उनसे पैसा निकाल लिये जाने के मामलों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कराया जाय। गरीबों के जीविकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा जो राशन दिया जा रहा है वह निरस्त हो रहा है और गरीब परिवार भुखमरी के कागार पर है। ऐसे में जांच कराकर जितने आधार कार्डो पर खरीद क्रय केन्द्रो द्वारा भुगतान किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी मे धूमधाम से मना राखी का त्यौहार

संवाददाता–बस्ती। उर्मिला एजूकेशनल एकेडमी में विगत वर्षो के भाति इस वर्ष भी भाई–बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विद्यालय की छात्राओं ने छात्रों की कलाई में राखी बांधकर उनके सुख–समृद्धि के लिए कामना किया। भाईयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया। राखी बांधने के बाद बहनों ने भाईयों को मिठाई भी खिलाया तथा भाईयों ने अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए उनको आकर्षक उपहार भेंट किये। विद्यालय के छात्राओं द्वारा पुलिस अधीक्षक गोपाल चौधरी को राखी बांधी गई तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। विद्यालय के प्रबन्ध निदेशक विनय शुक्ल प्रधानाचार्य नरेन्द्र सिंह और प्रधानाचार्या शशिप्रभा त्रिपाठी ने बच्चों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हुए पर्व की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर विद्यालय के आचार्य बसन्त गुप्ता, अभिनय प्रकाश पाण्डेय, श्रवण कुमार चौधरी, संतोष सिंह, राकेश पाण्डेय, सजंय प्रजापति, गंगेश सिंह, गंगेश शुक्ल, वकील चौधरी, राजेश पाण्डेय, संजय प्रजापति, शैल जी, अपूर्वा त्रिपाठी, सतनाम कौर, मधु, स्तुति मिश्रा, कमलोजन मिश्रा, नम्रता पाण्डेय, प्रेरण, शालिनी यादव आदि सहित सभी अध्यापक, अध्यापिकांए उपस्थित रहे।

"कार्ड बनाओ एवं राखी बनाओ" प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

संवाददाता–बस्ती। भाई बहन का अटूट प्रेम एवं पवित्र बंधन का संदेश देने वाला त्यौहार जी.वी.एम. कान्वेंट स्कूल में बड़े ही उत्साह एवं भाव के साथ मनाया गया। इसके अंतर्गत "कार्ड बनाओ एवं राखी बनाओ" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ो बच्चों ने उत्साह से प्रतिभाग किया एवं रंग बिरंगी राखियां बनाई। विद्यालय के प्रबंधक संतोष सिंह एवं प्रधानाचार्या विजयलक्ष्मी सिंह ने प्रतियोगिता का निरीक्षण किया। इस मौके पर संतोष सिंह ने बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए इस त्यौहार के महत्व पर प्रकाश डाला एवं राखी बनाने के गुण बताए। नर्सरी के बच्चों ने भी बड़े ही उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधी और भाइयों ने बहनों को चॉकलेट उपहार स्वरूप दिया। कक्षा एक से प्रिसिका,अनन्या एवं अपूर्वा प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय रहे। कक्षा दो से अर्चिता,अलीशा,प्रियांशी प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय रहे। कक्षा तीन से प्रखर,इलहम,शिवांशी,प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्षा चार से सुकृति,अंकित,रिद्धि प्रथम,द्वितीय,तृतीय कक्षा पाँच से अब्दुल,अविष्का,वर्षा प्रथम द्वितीय तृतीय रहे. कक्षा छरू से साल्वी,अंशिका,यश प्रथम, द्वितीय,तृतीय रहे। कक्षा सात से दीपक, सिद्धि, श्रद्धा चौधरी प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। कक्षा आठ से राजश्री,सक्षम,नीरज प्रथम द्वितीय एवं तृतीय रहे. कक्षा नौ से दिव्या, जान्हवी, आरूषि, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय रहे। कक्षा दस से सपना एवं ज्योति प्रथम अविका द्वितीय एवं यशिका और प्रतिष्ठा तृतीय रहे। कक्षा ग्यारह से अमूल्या,नित्या, एवं अंशिका सामूहिक रूप से प्रथम रहे। निर्णायक मंडल में प्रधानाचार्या विजय लक्ष्मी सिंह, अनन्या,प्रवीन,रिचा एवं रुबीना रहे। इस अवसर पर राकेश, राजेश, शैलेंद्र, सुधांशु, विजय गुप्ता, निगहत,हिना, रागिनी, अनीता, शिवांगी, किरन,ममता,सावित्री, सुधीर,गिरीश,नम्रा,सहित अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

दिल्ली व कोलकाता की बनी राखियों से पटा बाजार

संवाददाता–महराजगंज। भाई–बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आने से राखियों का बाजार गरम होने लगा है। महराजगंज शहर में आकर्षक राखियों को सजा दिए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर महराजगंज शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में रंग–बिरंगी राखियों और मिठाइयों की वेराइटी की भरमार है। महराजगंज शहर में दिल्ली, कोलकाता की बनी राखियों से पूरा बाजार पटा हुआ है। महंगाई के बाद भी स्टोन, जरकन, मेटल की राखी, कलावा के साथ रूद्राक्ष की फैंसी राखी लोग अधिक खरीद रहे हैं। महिलाएं, लड़कियां खरीदारी को लेकर काफी उत्साहित हैं। प्रधान डाकघर में राखी पोस्ट कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कई महिलाओं ने तो कोरियर के माध्यम से मिठाई, राखी भेज दिया है। रक्षाबंधन के मौके पर परिवहन निगम ने भी पूरे प्रदेश की महिलाओं को सफर में निरूशुल्क सुविधा मुहैया करा दिया है। महिलाएं 18 अगस्त की रात्रि 12 बजे से लेकर 19 अगस्त रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर करेंगी। इस साल रक्षाबंधन का पर्व पांच महायोग के बीच मनाया जाएगा। आर्यावर्त ज्योतिष विज्ञान के संस्थापक आचार्य लोकनाथ तिवारी ने बताया कि इस साल 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में राखी बांधने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी रहेगा और इस काल में राखी बांधना अशुभ हो सकता है। आचार्य ने बताया कि 19 अगस्त को दोपहर में 1 बजकर 25 मिनट से लेकर रात्रि में 12 बजकर 28 मिनट तक राखी बांधना अत्यंत ही शुभ माना जाएगा। आचार्य दीपक उपाध्याय ने बताया कि रक्षा बांधने के लिए रेशम, सूती वस्त्र और धागे का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वह रंगीन पीले या केसरिया रंग का हो।

प्रॉमिनेंट पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया

संवाददाता–अयोध्या। प्रोमिनेंट पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया तथा प्रबंधक राघवेंद्र अवस्थी तथा शिक्षकों के नेतृत्व में एक रैली संस्था से विद्या कुंड चौराहे तक निकाली गई, जिसमें बच्चे स्वतंत्रता दिवस अमर रहे ,वंदे मातरम, जय हिंद आदि के नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा प्रस्तुत नन्हा मुन्ना राही हूं ,चंदा ने पूछा तारों से ,फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ,देश रंगीला ,संदेशे आते हैं आदि देशभक्ति गानों की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया। उक्त अवसर पर अभिभावक,पत्रकार संपादक शिवकुमार मिश्रा, देवकीनंदन चतुर्वेदी तथा शिक्षक संदीप यादव, उषा मिश्रा, पूजा निषाद ,रत्ना, समृद्धि, खुशी, अनीता सोनकर, नीलम गुप्ता तथा प्रधानाचार्य संगीता उपस्थित थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुस्कान पुनर्वास केंद्र कनीगंज अयोध्या के मूक बधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों ने न केवल तिरंगा यात्रा में भाग लिया वरन् संस्था में रंगा रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें माइम भारत मां हमें भी सीमा पर जाकर देश की रक्षा करनी है। हमें भी क्रांतिवीर बनना है,नशा जहर है ,टिका लगाए दिव्यांकता से बचाये।

राजकीय महिला शरणालय में दी गई भ्रूण हत्या की जानकारी

संवाददाता–गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सोमवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में लिंग चयन और लिंग निर्धारण के निषेध पर जन जागरूकता एवं कन्या भ्रूण हत्या व बालिकाओं के प्रति भेदभाव विषय पर विधिक जागरूकताध साक्षरता शिविर का आयोजन राजकीय महिला शरणालय घंटाघर में किया गया। यह जानकारी अपर सत्र न्यायाधीशध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास सिंह ने दी। उन्होंने सर्वप्रथम महिला शरणालय का औचक निरीक्षण किया तथा उपस्थित संवासिनियों को उक्त विषय पर लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के बारे में बताया कि यह कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण का विज्ञापन करता है या ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होता है तो उसे तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त महिला शरणालय के निरीक्षण केवदौरान समक्ष आई कमियों के सुधार के लिए प्रभारी को निर्देशित किया कि वह शरणालय का नियमित रूप से साफ सफाई करवाते रहे। साथ ही साथ यदि किसी संवासिनी को किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो उनका प्रार्थना पत्र तैयार कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध कराए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, शक्ति शंकर द्वारा फाईन आफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्शीपुर, जनपद–गोरखपुर से मुद्रित कराकर, मुहल्ला–द्वितीय तल पुष्पांजलि काम्प्लेक्स शाही मार्केट, गोलघर, जनपद–गोरखपुर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक :
शक्ति शंकर
मो नं.
7233999001
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा।